RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : रविवार 24 दिसंबर 2023 | वर्ष 05 | अंक 241 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

राज्य के सैकड़ों मराठा छात्रों को हाई कोर्ट से राहत...

तीन साल से रुकी पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द कर दिया कि मराठा समुदाय के उम्मीदवार आर्थिक पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।

पीठ ने 'मैट'फैसले को रद्द करते हुए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और चार सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करने का निर्देश दिया. कोर्ट के इस फैसले से सैकड़ों मराठा छात्रों को राहत मिली है क्योंकि पिछले तीन दिनों से रुकी लोक सेवा आयोग, वन विभाग, कर सहायक, पुलिस उपनिरीक्षक, इंजीनियर और अन्य पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. वर्षों को साफ कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए 2018 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के तहत, राज्य में मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया गया था; हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार दिया। राज्य सरकार ने 2019 में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।

इस विज्ञापन में मराठा अभ्यर्थियों के लिए 'एसईबीसी'के अंतर्गत आरक्षण रखा गया; हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसईबीसी अधिनियम को रद्द करने के बाद, जिन उम्मीदवारों ने मूल रूप से इसके तहत आवेदन किया था, उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने इस आशय का एक अध्यादेश भी जारी किया; लेकिन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत पहले ही आवेदन कर चुके गैर-मराठा उम्मीदवारों ने इस अध्यादेश को मैट में चुनौती दी और नियुक्ति रद्द करने की मांग की.मैट ने एसईबीसी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह कहकर अयोग्य घोषित कर दिया था कि वे ईडब्ल्यूएस के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। फरवरी 2023 में मैट के इस रिजल्ट को सैकड़ों मराठा उम्मीदवारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. आज जज नितिन जामदार और जज मंजूषा देशपांडे की बेंच के सामने सुनवाई हुई.

कोर्ट ने क्या कहा?

1. सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को अनुमति देकर स्थिति को संभालने की कोशिश की गई.
2. मैट ने अपने आदेश में कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला है कि राज्य की कार्रवाई मनमानी है।
3. रिजल्ट के मुताबिक मराठा समुदाय के उम्मीदवारों ने अधिक अंक हासिल किए, जिसका मतलब है कि वे कभी भी एसईबीसी आरक्षण के लिए पात्र नहीं थे।
4. मैट का निर्णय स्थापित कानूनी सिद्धांतों से भटकता है और गलत है। इस आदेश का अभ्यर्थियों पर नकारात्मक असर पड़ा.

40 लाख रुपये का गुटखा जब्त, एक युवक गिरफ्तार

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 40 लाख रुपये का गुटखा जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। महाराष्ट्र में गुटखे का निर्माण और बिक्री दोनों प्रतिबंधित है। निरीक्षक डी.टी. सोंके ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बृहस्पतिवार को गणेशपुरी थाना क्षेत्र में एक टेम्पो को रोका और भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया। अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित वस्तु को ले जा रहे 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया और मामले की जांच जारी है।

दाऊद इब्राहिम के मुंबई और रत्नागिरी वाले बंगले होंगे नीलाम...

5 जनवरी को लगेगी आम के बगीचों की भी बोली

मुंबई: दाऊद इब्राहिम कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में जहर दिए जाने की अफवाहों की वजह से सुर्खियों में था। हालांकि मुंबई पुलिस ने इन खबरों को फर्जी करार दिया था, लेकिन उसके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई बरकरार है। तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम के तहत उसकी रत्नागिरी की कई संपत्तियों की 5 जनवरी को नीलामी की जाएगी। केंद्र सरकार के इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन भी दिया गया है। नीलामी दोपहर 2 से 3.30 बजे होगी। कुछ साल पहले रत्नागिरी के खेड़ तालुका में बंगले और आम के बागों सहित कुल चार संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। इन्हीं की अगले महीने नीलामी होगी। दाऊद की 11 संपत्तियों की पहली बार नीलामी साल 2000 में इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई थी, लेकिन तब नीलामी प्रक्रिया में कोई भी नहीं आया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जांच एजेंसियां दाऊद की कई प्रॉपर्टी बेचने और खरीदारों को कब्जा भी दिलवाने में कामयाब रहीं।

महाराष्ट्र में नशे पर नकेल का प्रयास...

11 महीने में 723 FIR, हैरान कर देगा गिरफ्तारी का आंकड़ा

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में इस साल एक जनवरी से 28 नवंबर तक नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए 859 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में 723 मामले दर्ज किए गए हैं. अधिकारियों ने ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान ड्रग तस्करों से 4.01 करोड़ रुपये की ड्रग्स और अन्य वस्तुएं जब्त की गईं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध)

पंजाबराव उगले की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नशा विरोधी समन्वय समिति की हालिया बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा ये आंकड़े उपलब्ध कराए गए और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

निरीक्षक ठाणे पुलिस के मादक द्रव्य विरोधी सेल के संजय शिंदे ने कहा, 1 जनवरी से 28 नवंबर के बीच ठाणे जिले में ड्रग्स से संबंधित कुल 723 अपराध दर्ज किए गए. इन मामलों में 859 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और ड्रग-तस्करों से 4,01,94,718 रुपये की ड्रग्स और सामान जब्त किए गए. बैठक के दौरान अधिकारियों को बंद रासायनिक इकाइयों का निरीक्षण तेज करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मेडिकल स्टोर डॉक्टरों की सलाह के बिना कफ सिरप और ऐसी अन्य दवाएं न बेचें. शिंदे ने कहा, उन्होंने अधिकारियों से जिले के विभिन्न जल निकायों के लैंडिंग बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखने को कहा.

मीरा रोड में महिला ने सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली

भयंदर: मानसिक तनाव में चल रही एक महिला ने गुरुवार को मीरा रोड में एक इमारत की सातवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मीरा रोड के शांति गार्डन में म्हाडा होम कॉम्प्लेक्स के निवासी ताहुरा अमान खान (उम्र 38 वर्ष) कुछ वर्षों से

मानसिक तनाव से पीड़ित थे। उनका भी इलाज किया जा रहा था. दो दिन पहले, वह बेवर्ली पार्क में मैरी गोल्ड बिल्डिंग में अपने घर गई थी। वह अचानक सातवीं मंजिल पर स्थित घर की गैलरी से नीचे कूद गया। परिवार वाले उसे पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मीरा रोड पुलिस जांच कर रही है।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

उपराष्ट्रपति की मिमिक्री

संसद परिसर में ही उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के सार्वजनिक अपमान पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहना पड़ा कि यह 'अशोभनीय आचरण' है। राष्ट्रपति व्यथित हुईं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पीड़ा साझा की कि वह 20 साल से ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार झेल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने गए और सांसदों के आपत्तिजनक व्यवहार पर गहरी चिंता जताई। उपराष्ट्रपति के अपमान पर देश भर से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वे सुर्खियां बनी हैं। भारत के 'संवैधानिक त्रिमूर्ति' को संसद परिसर में ही क्षोभ जताना पड़ा है। यह लोकतंत्र और संविधान का भी अपमान है। संसद परिसर किसी विदूषक, कॉमेडियन, जोकर या नकलची का मंच नहीं है। बेशक संसद के दोनों सदनों से 143 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया है। सांसद संसद के प्रवेश-द्वार पर बैठे हैं। वे संसद भवन से विजय चौक या राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल सकते थे अथवा जंतर-मंतर पर मॉक संसद का आयोजन कर अपना विरोध जता सकते थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के हाव-भाव और भंगिमाओं की नकल कर उनका मजाक उड़ाया। क्या सांसद के नाते यही संस्कार और आचार-संहिता सीखी है उन्होंने? कल्याण भी विदूषक या जोकर नहीं हैं, जो नकल करने की कला पर निलंबित सांसदों को हंसा रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उस 'मिमिक्री' का वीडियो बना रहे थे। क्या उन्हें 'संवैधानिक चेहरे' की खिल्ली उड़ाने में सुख मिलता है? यह देश का भी अपमान है। राहुल गांधी भी उपराष्ट्रपति के अपमान में शामिल दिखे। चूंकि मोदी सरकार अडाणी समूह, बेरोजगारी, महंगाई सरीखे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर सरोकार नहीं जता रही है, तो इसके मायने ये नहीं हो सकते कि राज्यसभा के सभापति को सरेआम बेइज्जत करें।

आखिर इस मजाक और अपमान के तर्क क्या हैं? उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। जगदीप धनखड़ निर्वाचित होकर पदासीन हुए हैं। कल्याण बनर्जी कुछ भी सफाई दें, लेकिन राज्यसभा के सभापति के प्रति उनका आक्रोश, उनकी खीझ और नफरत ही अभिव्यक्त हुई हैं। संसद परिसर में यह व्यवहार अक्षम्य है। संभव है कि राज्यसभा के निलंबित सांसद, सभापति के फैसले से, असहमत और असंतुष्ट हों! ज्यादातर सांसद लोकसभा से निलंबित किए गए हैं। हमने ऐसी कार्रवाई का विश्लेषण किया था और इन्हें 'कठोरतम कर्रवाई' करार दिया था। ऐसी कार्रवाई की जाएगी, तो संसद विपक्ष-मुक्त होने लगेगी। यह भी संवैधानिक स्थिति नहीं है, लेकिन इन पीठासीन अध्यक्षों के फैसलों के बदले में संवैधानिक चेहरों का अपमान भी बिल्कुल अस्वीकार्य है। हमें याद नहीं आता कि ऐसा सार्वजनिक अपमान संसद परिसर में पहले कभी किया गया हो!

बहरहाल अब इस अपमान की सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जाट समाज की खाप के प्रधान जगदीप सेहरावत ने कहा है कि यह उपराष्ट्रपति ही नहीं, देश के किसानों का भी अपमान है। खाप ने माफी मांगने का आग्रह किया है। अन्यथा किसान और जाट मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सर्वोच्च अदालत के अधिवक्ता विनीत जिंदल ने विवादास्पद सांसदों के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा की आचार समितियों में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कल्याण, राहुल और अन्य सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यह संसद में जातीयता का मुद्दा नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद और सदन के संरक्षक की गरिमा को कैसे गिराया जा सकता है? यदि भाजपा ने जाट और किसान अपमान का भी मुद्दा बना लिया, तो गौरतलब है कि देश भर में 9 करोड़ से अधिक, करीब 6.5 फीसदी आबादी, जाट हैं।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

दक्षिण मुंबई में फुटपाथ और रास्तों से अतिक्रमण हटाओ...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी से कहा

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दक्षिण मुंबई में फुटपाथ और रास्तों से अतिक्रमण हटाने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश मुंबई निवासी धरम वल्लकती की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि कमाठीपुरा और एसपी रोड के लेन 1 से 16 के बीच फेरीवालों ने अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर

रखा है, जिससे स्थानीय रहिवासियों और राहगीरों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। याचिका के अनुसार, 2018 से लगातार कई बार बीएमसी से इस संबंध में शिकायत की जा रही है, मगर अब तक अतिक्रमण को हटाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जबकि जिन लेन पर हॉकर ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। वे लेन नॉन हॉकिंग जोन (फेरीवालों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आती हैं। इसके बावजूद वहां फेरीवालों की गतिविधियां जारी हैं और प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। यह स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे लोगों को आए दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

'15 दिन में ले निर्णय'

चीफ जस्टिस डी.के उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने याचिका में उठाई गई समस्या को देखते हुए याचिकाकर्ता को 15 दिन के भीतर बीएमसी की उपयुक्त अथॉरिटी के सामने अपना विस्तृत रिप्रेजेंटेशन (निवेदन) रखने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने दावे को लेकर सभी जरूरी दस्तावेज जोड़ें, जबकि बीएमसी याचिकाकर्ता के निवेदन पर तत्परता से विचार करे। साथ ही उन इलाकों, रास्तों और फुटपाथ से फौरन अतिक्रमण को हटाए, जिनका याचिका में जिक्र किया गया है।

मैट में खाली पदों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मैट) में खाली पदों को भरने में हुई प्रगति पर जवाब मांगा है। साथ ही सरकार को मैट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूर एक करोड़, 39 लाख रुपये की राशि को शीघ्रता से जारी करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डी.के उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने यह निर्देश कन्हैया महामुनि की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया।

सेक्स रैकेट में फंसी 2 नाबालिक बहनों को पुलिस ने छुड़ाया

दलाल महिला गिरफ्तार

मुंबई : मजबूरी इंसान से क्या काम करवाए यह कोई नहीं बता सकता। कुछ ऐसी ही एक घटना मुंबई के मुलुंड से सामने आई है। जी हां दरअसल मुलुंड में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 14 और 17 साल की दो बहनों की खराब आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उन दोनों बहनों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में मुलुंड पुलिस ने देह व्यापार की दलाल श्वेता गोलवलकर (34) को गिरफ्तार किया है। बचाई गई दोनों लड़कियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इस मामले में दलाल महिला के खिलाफ अनैतिक व्यापार के उद्देश्य से अपहरण के साथ ही पॉक्सो के तहत कार्रवाई की गई है। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि महिला को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। इस मामले में मुलुंड पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, इस दलाल महिला द्वारा लड़कियों को पैसों का लालच देकर सेक्स रैकेट में शामिल किया गया है। श्वेता गोवलकर ठाणे इलाके में रहती हैं। वह घर का काम करती है। चौंकाने वाले इस मामले में मुलुंड पुलिस को जानकारी मिली कि वह नाबालिग लड़कियों को पैसे का लालच देकर ग्राहकों के पास भेज रही है। यह घटना तब सामने आई जब मुलुंड पुलिस ने गुरुवार दोपहर मुलुंड के चेकनाका में एक होटल से देहव्यापार में पड़ने से इन दो लड़कियों को बचाया। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

महाराष्ट्र के लातूर में कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 4 लोगों की मौत!

लातूर : महाराष्ट्र के लातूर जिले में औसा के समीप शुक्रवार तड़के एक तेज रफ्तार कार एक ट्रैक्टर से टकरा गई। इस घटना में तीन शिक्षकों सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कार में सवार लोग रात का खाना खाने के बाद तुलजापुर-औसा राजमार्ग पर शिवली से औसा की ओर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूटकर 30 फीट दूर जा गिरा।

पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान देवनी तहसील के विलेगांव निवासी और औसा तहसील के खरोसा केंद्रीय विद्यालय के मुख्याध्यापक संजय रणदिवे (41), खरोसा निवासी जयप्रकाश बिराजदार (45), किल्लारी निवासी महबूब पठान (45) और कार चालक राजसेब बागवान (34) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस, स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय लोगों ने सुबह करीब साढ़े चार बजे क्रेन की मदद से क्षत-विक्षत शवों को कार से बाहर निकाला।

विरार में 20 लाख की एमडी जब्त

नालासोपारा: विरार अपराध जांच दस्ते ने 20 लाख रुपये (एमडी) मूल्य की दवाएं जब्त की हैं और दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके खिलाफ विरार पुलिस स्टेशन में 'एनडीपीएस' के तहत मामला दर्ज किया गया है. वसई कोर्ट ने आज (22 तारीख) उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया। ड्रग तस्करों के नाम मोहम्मद इशाक शेख (उम्र 34), मोहम्मद मोइनिदुन शेख (उम्र 25, दोनों धारावी, मुंबई) हैं। विरार अपराध जांच दस्ते को सूचना मिली थी कि आरोपी गुरुवार को

विरार ईस्ट मोहॉक सिटी इलाके में ड्रग्स बेचने आएंगे। तदनुसार, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले ने तुरंत पुलिस उप-निरीक्षक ज्ञानेश्वर कोकाटे, पुलिस कांस्टेबल सचिन लोखंडे, विशाल लोहार, संदीप शेरमाले, योगेश नागरे, पुलिस प्रवर्तन अधिकारी बालाजी गायकवाड़, सचिन बालिद, प्रफुल्ल सोनार की एक टीम बनाई। इस टीम की गश्त के दौरान बुलेट से आए संदिग्धों को टीम ने रोका. उसके शरीर की तलाशी के दौरान 19 लाख 40 हजार रुपये कीमत की 97 ग्राम एमडी मिली. इनके पास से एमडी और एक गोली समेत 20 लाख 90 हजार 630 रुपये का सामान जब्त किया गया है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कांबले ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि वे ये दवाएं कहां से लाए और कहां बेचने जा रहे थे।

150 करोड़ के घोटाले में विधायक सुनील केदार को पांच साल कैद की सजा और 10 लाख का लगा जुमार्ना

मुंबईः अदालत ने कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुनील केदार और पांच अन्य को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) में धन के दुरुपयोग के लिए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे वी पेखले-पुरकर ने 2002 के इस मामले में फैसला सुनाया है. छह लोगों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपियों में केदार के अलावा एनडीसीसीबी के महाप्रबंधक और निदेशक और एक निवेश फर्म होम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक शामिल हैं. इस केस में तीन लोगों को बरी कर दिया गया है.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, विश्वास का ऐसा आपराधिक उल्लंघन एक गंभीर अपराध है. अदालत ने कहा कि इतनी बड़ी रकम का नुकसान बैंक की वित्तीय स्थिति को नीचे लाने के लिए पर्याप्त है, जिसका असर इकाई के हजारों सदस्यों और कर्मचारियों पर पड़ेगा. अदालत के आदेश में कहा गया है कि उच्च पदों पर बैठे लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि किसी सदस्य का एक भी रुपया किसी भी तरह से बर्बाद न हो. अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी व्यक्तियों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती. मामले

में भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120बी और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 248 के तहत सजा पाने वालों में केदार, महाप्रबंधक अशोक चौधरी, केतन सेठ, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी और नंदकिशोर त्रिवेदी शामिल हैं.

58 साल के विधायक सुनील केदार ने साल 2019 में महाराष्ट्र के सावनेर से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की. आजकल वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा, वह पांच बार सावनेर निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गए. सुनील छत्रपाल केदार सावनेर से कांग्रेस विधायक हैं. उनका जन्म नागपुर में हुआ था और वर्तमान में वे सावनेर, नागपुर में रहते हैं. अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो वह स्नातकोत्तर हैं और व्यवसायी, कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं.

अन्य प्रावधानों के अलावा, केदार को भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात) के तहत दोषी ठहराया गया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, एनडीसीसीबी को 2002 में सरकारी प्रतिभूतियों में 125 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि होम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धन निवेश करते समय नियमों का उल्लंघन किया गया था. तब केदार बैंक के अध्यक्ष थे. अपने फैसले में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेखले-पुरकर ने कहा कि केदार और एक अन्य आरोपी को बैंक की पूरी हिस्सेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने कहा कि विचाराधीन फंड बैंक के लोगों और सदस्यों की मेहनत की कमाई थी, जिनमें से अधिकांश लोग यहां के गरीब किसान हैं.

कंटेनर की टक्कर से राहगीर महिला की मौत

भिवंडी : शाम करीब 5.30 बजे एक घटना घटी जब भिवंडी से वाडा की ओर जा रहे एक कंटेनर ने तालुका के कुदुस नाका पर एक महिला पैदल यात्री को टक्कर मार दी। मृत महिला का नाम देवी भूपेन्द्र शर्मा है. चूंकि शुक्रवार को कुदुस में साप्ताहिक बाजार लगता है, इसलिए नाका पर काफी भीड़ रहती है. सड़कों पर जाम लगने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं. इसके अलावा सड़क के दोनों ओर ठेले लगे होने से नागरिकों को हाथ में हाथ रखकर सड़क पार करना पड़ता है। बाजार से निकल रहे देवी शर्मा की कंटेनर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गयी.

पालघर में दो वाहनों की टक्कर में दो की मौत

पालघर : पालघर जिले के बोइसर इलाके में एक टेंपो और ट्रेलर ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना बोइसर-चिल्लर रोड पर वारंगडे गांव में तब हुई जब माल से लदा टेंपो गुजरात से मुंबई की ओर जा रही थी जबकि ट्रक विपरीत दिशा से आ रहा था। बोइसर पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि चालक समेत टेंपो में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

नीतीश कुमार को फोन मिलाने के बाद राहुल गांधी ने अब शरद पवार से की मुलाकात...!

महाराष्ट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार (22 दिसंबर) को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार से मुलाकात की. दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब नई दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार (19 दिसंबर) को ही विपक्षी गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक हुई थी. गठबंधन इंडिया की मीटिंग में सीट शेयरिंग, साझा रैली और पीएम फेस सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई. विपक्षी गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल सीट शेयरिंग को लेकर ही माना जा रहा है. ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शरद पवार की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है.

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सीट बंटवारा करना बड़ी चुनौती है. यहां पर महाविकास अघाडी यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच पहले से ही गठजोड़ है. ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किसके पास कितनी सीटें जाती हैं? महाराष्ट्र के अलावा यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में भी सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने सवाल है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं. राहुल गांधी ने गुरुवार (21 दिसंबर) को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की थी. दोनों नेताओं की ऐसे समय पर फोन पर बात हुई थी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पीएम फेस के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का नाम आगे करने को लेकर अटकलें थी कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं. हालांकि इसे जेडीयू खारिज कर चुकी है. कई मौके पर नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि वो पीएम की रेस में नहीं हैं. कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने गुरुवार को ही अपने प्रस्ताव में कहा कि वह बहुत जल्द उम्मीदवारों का चयन कर लेगी और विपक्षी गठबंधन इंडिया को बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी ढाल बनाने के लिए कदम उठाएगी. ऐसे में राहुल गांधी की नेताओं से बातचीत को इसी कड़ी में देखा जा रहा है.

महाराष्ट्र पर मंडरा रहा जल संकट! बांधों में बचा 64 फीसदी पानी, यहां स्थिति चिंताजनक

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को आगामी महीनों में पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। आंकड़ों से पता चला है कि राज्य के बांधों में 64 फीसदी जल भंडारण है। सबसे बुरा हाल मराठवाडा का है, जहां बांधों में सबसे कम जल भंडारण है। पिछले साल की तुलना में पुणे, नासिक, नागपुर और अमरावती डिविजन के बांधों में पानी का भंडारण कम होने की बात सामने आई है। औरंगाबाद डिविजन के बांधों में सबसे कम 37 फीसदी जल भंडारण है। जानकारी के अनुसार, पिछले साल आज के दिन तक राज्य के बांधों में 85 फीसदी जल भंडारण बचा था। लेकिन इस साल 64 फीसदी पानी का भंडार बचा हुआ है। इसका मुख्य कारण पर्याप्त बारिश न

होना बताया जा रहा है। इससे राज्य पर जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोंकण क्षेत्र के जलाशयों में सर्वाधिक पानी बचा है। कोंकण के बांधों में 79 फीसदी पानी का भंडारण बचा हुआ है। जबकि सबसे कम पानी औरंगाबाद के बांधों में बचा है। इससे मराठवाडा में पानी की समस्या गंभीर होने की आशंका है।

पुणे संभाग के बांधों में 67 फीसदी पानी का भंडारण बचा हुआ है। जबकि नासिक डिविजन के बांधों में 68 प्रतिशत पानी शेष है। अमरावती डिविजन के बांधों में 74 प्रतिशत, तो नागपुर डिविजन के बांधों में 69 फीसदी पानी रह गया है। वहीं, कोंकण डिविजन के बांधों में 79 फीसदी जल भंडारण अभी भी है। औरंगाबाद डिविजन के बांधों में सबसे कम 37 फीसदी जल भंडार है। जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र में इस साल कुल बारिश औसत से 13.4 फीसदी कम हुई है। महाराष्ट्र में आधिकारिक तौर पर मॉनसून 1 जून से शुरू होता है और आम तौर पर 30 सितंबर तक रहता है। इस साल राज्य के कम से कम 9 जिलों में औसत से बहुत कम बारिश हुई है। हालांकि कोंकण-गोवा बेल्ट में औसत से करीब 18 फीसदी ज्यादा बारिश हुई।

दिव्यांग लड़की से यौन शोषण करने वाला गिरफ्तार

मलाड : मालवणी पुलिस ने 13 साल की विकलांग लड़की से बलात्कार के आरोप में 37 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

महाराष्ट्र में कड़ाके की ठंड... शीतलहर के प्रकोप में कई इलाके

मुंबईः महाराष्ट्र में ठंड बढ़ गयी है. विदर्भ में शीतलहर देखने को मिल रही है. दक्षिण भारत में पिछले कुछ हफ्तों से भारी बारिश हो रही है. पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है. मैदानी इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण महाराष्ट्र के वातावरण पर भी असर पड़ रहा है. विदर्भ के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. क्रिसमस के बाद कुछ दिनों तक तापमान बढ़ने की संभावना है. इसके बाद तापमान में फिर से कमी आएगी.

परभणी जिले में पिछले 4 दिनों से शीतलहर चल रही है और जिला कड़ाके की ठंड से प्रभावित है.लगातार दूसरे दिन जिले का तापमान गिरकर 10.08 डिग्री पर आ जाने से सभी जगह भीषण ठंड

का माहौल बन गया है. शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी अलाव जलने शुरू हो गये हैं. ठंड से बचाव के लिए नागरिक गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि ठंड रबी फसलों के लिए फायदेमंद है.<दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक जिले में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी, इसलिए रबी सीजन की फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की आशंका है. लेकिन पिछले एक सप्ताह में जिले में तापमान में गिरावट आयी है और ठंड का प्रकोप बढ़ गया है. पिछले तीन दिनों से तापमान में काफी गिरावट आई है और तापमान 15 डिग्री पर आ गया है. वातावरण में ओस रहने से रबी सीजन की फसलों को फायदा होगा और फसलों के लिए अनुकूल वातावरण बना है. लेकिन ठंड बढ़ने के कारण नागरिकों को ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है.

पिछले दो दिनों से वातावरण में आए बदलाव के कारण नासिक जिले में ठंड का एहसास होने लगा है, नागरिकों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है. नासिक के ग्रामीण इलाकों में लोग इस ठंड से बचने के लिए गर्म-गर्म कपड़े पहनने लगे हैं. तो हर तरफ आग जलती नजर आती है.

पनवेल नगर निगम क्षेत्र के खारघर कॉलोनी में कोरोना का पहला मरीज

पनवेल: पनवेल नगर निगम क्षेत्र के खारघर कॉलोनी में गुरुवार को पहला कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाया गया. शुक्रवार को मनपा स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों के निर्देश के बाद पीड़ित अपने घर पर ही होम आइसोलेशन में रहा और उसका इलाज चल रहा है. नगर पालिका के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि खारघर कॉलोनी के सेक्टर 16 स्थित वास्तुविहार बिल्डिंग में रहने वाला 33 वर्षीय व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित था. आनंद गोसावी ने कहा. साथ ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग को शुक्रवार को कलंबोली कॉलोनी में स्वाइन फ्लू का एक मरीज मिला है. मनपा आयुक्त गणेश देशमुख ने अपील की है कि महामारी संबंधी बीमारियों के बढ़ने के कारण शहरवासी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले मास्क का उपयोग करें.

कोरोना महामारी के लिए पनवेल

नगर निगम तैयार है

पनवेल मनपा के स्वास्थ्य विभाग में कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मरीज पाए जाने के बाद राज्य सरकार के निदेशांनुसार मनपा आयुक्त ने मनपा प्रशासन सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है. . नगर निगम में श्वसन गैस की क्षमता के साथ पर्याप्त दवा भंडार, साथ ही सरकारी उपजिला अस्पताल और पनवेल नगर निगम क्षेत्र के निजी अस्पतालों में बीमार बिस्तरों की समीक्षा की गई है। पनवेल नगर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनपा आयुक्त गणेश देशमुख ने आनंद गोसावी के साथ हुई बैठक में बताया कि पनवेल मनपा क्षेत्र में कोरोना के लिए 1291 बेड उपलब्ध हैं. इसमें 789 हवादार बिस्तर, 258 गहन देखभाल बिस्तर, 94 वेंटिलेटर बिस्तर और 244 गैर हवादार बिस्तर हैं। हालांकि अभी तक किसी को भी मास्क पहनने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाते समय मास्क पहनना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, बुखार, सर्दी, खांसी के मरीजों को नगर निगम द्वारा शुरू किए गए आरोग्यवर्धिनी केंद्र से इलाज कराना चाहिए। - **गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल नगर पालिका**

नेरुल, सरसोले गांव में दुर्गंधयुक्त गंदे पानी की शिकायत... लेकिन नगर निगम प्रशासन ने शिकायत से कर दिया इनकार

नवी मुंबई: नेरुल, सारसोले डिविजन में गंदा और बदबूदार पानी की शिकायतें आ रही हैं. हालांकि, मनपा प्रशासन का दावा है कि सारासोले महकमा में जलापूर्ति ठीक से हो रही है. 16 दिसंबर से सरसोले गांव में गंदा और बदबूदार पानी आने की शिकायत आ रही है। सारसोल गांव की महिलाओं ने इसकी शिकायत की है और कहा है कि नल से मटमैला पानी आ रहा है और पानी से गंदी बदबू भी आ रही है. सवाल पूछा जा रहा है कि नल का मटमैला पानी कैसे पियें।

लोकसभा सीट में से 23 पर लड़ेगी उद्धव सेना

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 23 सीट पर चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने कहा कि इस सप्ताह के शुरू में राष्ट्रीय राजधानी में विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई थी।

राज्यसभा सदस्य ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से बातचीत की थी।

संजय राउत ने कहा, 'हम 23 सीट पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम हमेशा इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ते हैं।' शिवसेना (यूबीटी), महा विकास आघाड़ी (एमवीए) का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस और शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) घटक हैं। तीनों दल विपक्षी गठबंधन 'इंडियन

नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस'(इंडिया) का भी हिस्सा हैं।

विंटर एप्लायंसेज फेस्ट - रूम हीटर, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर और अन्य पर न्यूनतम 40% की छूट।

संजय राउत ने इस सवाल पर टिप्पणी नहीं कि कांग्रेस और एनसीपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा, 'सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। यह (बातचीत) दिल्ली में होगी क्योंकि महाराष्ट्र में कोई (कांग्रेस) नेता नहीं है जो फैसला ले सके। और अगर नेता है तो उसके पास फैसला करने का अधिकार नहीं है। उन्हें दिल्ली से पूछना ही होगा।'

अविभाजित शिवसेना ने 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ मिलकर 23 सीटों पर लड़ा था जिनमें से 18 पर उसे जीत मिली थी। इन 18 सांसदों में से अब 13 सांसद शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले गुट के साथ हैं। शिवसेना का पिछले साल जून में विभाजन हो गया था।

मुलुंड स्टेशनों पर पहला वुलु शौचालय खुला

वुलु क्या है?

वुलू का कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों का है और इसमें महिलाओं के लिए टॉयलेट, सैनिटरी पैड, चाय-कॉफी, सिलाई किट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पानी की बोतलें, सैनिटाइजर, मधुर संगीत, चॉकलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए महिलाओं को शुल्क देना होगा. सौंदर्य प्रसाधन भी उपलब्ध रहेगा.

मुंबई: कुछ महीने पहले सेंट्रल रेलवे ने महिला यात्रियों के लिए छह रेलवे स्टेशनों पर निजी कंपनियों के हाईटेक महिला शौचालय शुरू करने का फैसला किया था. तदनुसार, गुरुवार से मुलुंड स्टेशन पर एक अलग महिला पाउडर रूम (वुलु) शुरू किया गया है। यहां महिलाओं को एक ही छत के नीचे सुरक्षा समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। उपनगरीय रेल को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जीवन रेखा माना जाता है। प्रतिदिन 75 लाख लोग उपनगरीय लोकल से यात्रा करते हैं। इसमें 20 लाख से ज्यादा महिला यात्री हैं. हालांकि, रेलवे स्टेशनों पर ज्यादातर महिला शौचालयों की हालत बेहद खराब है। इसलिए, अधिकांश महिला यात्री शौचालय का उपयोग करने से बचती हैं या केवल आपात स्थिति में ही इसका उपयोग करती हैं। महिला यात्रियों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, मध्य रेलवे ने एक निजी कंपनी की मदद से छह रेलवे स्टेशनों पर अत्याधुनिक महिला शौचालय शुरू करने का निर्णय लिया। इस संबंध में सबसे पहले खबर सकाल ने प्रकाशित की थी. इसके बाद गुरुवार से मुलुंड स्टेशन पर वुलू शुरू कर दिया गया है.

धूल में सनी टोइंग वैन के कारण सीवुड्स मॉल इलाके में अवैध पार्किंग की समस्या गंभीर है...

नवी मुंबई: नवी मुंबई शहर में पार्किंग की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और सीवुड्स उपनगर में सीवुड्स रेलवे स्टेशन के ऊपर के क्षेत्र में स्थित नेक्सस सीवुड्स ग्रैंड सेंट्रल मॉल के कारण पूर्व में बड़ी मात्रा में अवैध पार्किंग होती है। इस क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र. सवाल खड़ा हो गया है कि सीवुड्स स्थित ट्रैफिक कंट्रोल रूम द्वारा पहली बार जब्त की गई टोइंग वैन को कार्रवाई के लिए कब समय मिलेगा।

2009 के बाद से, सीवुड्स ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास अवैध पार्किंग से निपटने के लिए कोई टोइंग वैन नहीं है। लेकिन अब टोइंग वैन को

चौकी से बाहर लाया जा चुका है और ट्रैफिक विभाग को अभी तक कार्रवाई करने का समय नहीं मिला है. मॉल सीवुड्स रेलवे स्टेशन पर स्थित होने के कारण, रेलवे यात्रियों के साथ-साथ मॉल में आने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ी है। इसलिए, स्टेशन के चारों ओर दोनों दिशाओं में सड़कों पर हमेशा अवैध पार्किंग होती है। ऐसे में स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को भी घर जाने के लिए वाहनों की अवैध पार्किंग से होकर अपनी सोसायटी में जाना पड़ता है। उसी खंड में यातायात को नियंत्रित करने के लिए अगस्त 2009 में सीवुड्स सेक्टर 48 के गायमुख चौक पर एक यातायात नियंत्रण पोस्ट शुरू किया गया था। करीब 14 साल बाद ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट को टोइंग वाहन मिला है, लेकिन वह दो माह से पोस्ट के बाहर धूल में पड़ा है। सीवुड्स रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ लगातार ट्रैफिक जाम रहता है. मॉल के कारण आप इस क्षेत्र से पैदल भी नहीं जा सकते। दो माह से टोइंग वाहन ट्रैफिक पुलिस चौकी के बाहर खड़ा है।

मराठा आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार को अब और समय नहीं, मनोज जरांगे पाटील का ऐलान

मुंबई: मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटील ने शुक्रवार को साफ कर दिया है कि मराठा आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार को अब और समय नहीं दिया जाएगा। उनकी इस घोषणा के बाद मराठा समाज और राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि शनिवार को बीड में होने वाली मराठा समाज की सभा से कुछ रास्ता निकल सकता है। एहतियातन सरकार ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने मराठा समाज के प्रमुख लोगों को

नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं।

प्रशासन को अंदेशा है कि आरक्षण की मांग को लेकर मराठे मुंबई की ओर कूच कर सकते हैं। प्रशासन को ऐसी भी खबर मिली कि मराठा समाज के लोग ट्रैक्टर रैली निकाल कर मुंबई जाम करने की योजना बना रहे हैं, इसलिए प्रशासन की तरफ से ट्रैक्टर वाले किसानों को भी नोटिस जारी कर रहे हैं। सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा नोटिस भेजे जाने से मनोज जरांगे पाटील नाराज हैं। उन्होंने शुक्रवार को परभणी में मराठा समाज की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक हमने कोई रणनीति जाहिर नहीं की है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें नोटिस भेजी जा रही हैं। हम नोटिसों से घबराने वाले नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि नोटिस देना बंद करो, वरना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com